The Research Analytics
Volume 3, Special Issue 1, Jan 2026
ISSN (Online): 3107-6165

The Research Analytics
(A Peer Reviewed and Open Access Journal)

22

जनजातीय शिक्षा में NEP 2020 की भूमिका

डॉ. समीना कुरैशी*

*सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, जे.ई.एस. कॉलेज, फरहदा, बिलासपुर, (छत्तीसगढ़), भारत।
Pages No: 162-167

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) जनजातीय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य समावेशन, समानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह नीति आदिवासी छात्रों की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषाई विविधताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष बल देती है। इससे बच्चों की बुनियादी समझ, रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है, साथ ही वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़े रहते हैं। NEP 2020 में जनजातीय समुदाय के लिए स्थानीय भाषा आधारित पाठ्यक्रम, परंपरागत ज्ञान एवं सांस्कृतिक विषयवस्तु को शिक्षण योजना का हिस्सा बनाया गया है। साथ ही, नीति शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा के विस्तार, और अध्ययन सामग्री के स्थानीयकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाती है, जिससे सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्रों के आदिवासी बच्चों तक बेहतर शिक्षा पहुँच सके। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों, छात्रवृत्ति योजनाओं और विशेष शिक्षा अभियानों के माध्यम से शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता में वृद्धि करने का प्रयास किया गया है।

हालांकि, नीति के क्रियान्वयन में भौगोलिक दूरी, संसाधन सीमाएँ, भाषा विविधता और प्रशासनिक अड़चनों जैसी चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। इनके समाधान के लिए स्थानीय सहभागिता, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और नीति की समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है। समग्र रूप से NEP 2020 जनजातीय शिक्षा को मुख्यधारा में लाने, उनकी सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के अवसर प्रदान करने वाली दूरदर्शी एवं समावेशी नीति है।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) शिक्षा के क्षेत्र में समावेशन और समानता प्रदान करने वाली एक व्यापक और प्रभावशाली नीति है। यह नीति विशेष रूप से जनजातीय समुदाय

की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षा में गुणवत्ता और पहुंच को सुधारने का उद्देश्य रखती है। NEP 2020 मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देती है, जिसका लक्ष्य है कि कक्षा पाँच तक बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ाई मिले ताकि उनकी सीखने की क्षमता और समझ में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त, नीति में जनजातीय संस्कृति और परंपरागत ज्ञान को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने की वकालत की गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि शिक्षा उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप हो और वे अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहें। इस तरह की शिक्षा से विद्यार्थियों में आत्म-सम्मान बढ़ेगा और वे अधिक प्रभावी ढंग से सीख पाएंगे। नीति अध्यापक प्रशिक्षण में भी सुधार लाती है, जिसमें शिक्षकों को जनजातीय बच्चों की विशेष संवेदनशीलताओं और आवश्यकताओं को समझना सिखाया जाएगा। साथ ही, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देकर दूरदराज के जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को आधुनिक तकनीक से जुड़े शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। यह ब्रिजिंग कोर्स और उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से पिछड़े हुए छात्रों को मुख्यधारा में जोड़ने का भी प्रयास करती है। NEP 2020 के तहत छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय और अन्य वित्तीय सहायता योजनाएँ भी जनजातीय छात्रों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं ताकि उनकी शिक्षा के मार्ग में आने वाली आर्थिक बाधाएं दूर हो सकें।

इस नीति का उद्देश्य है शिक्षा को समावेशी, संवेदनशील और गुणवत्तापूर्ण बनाना, ताकि सभी जनजातीय बच्चे समान अवसरों के साथ आगे बढ़ सकें और अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकें। इस प्रकार, NEP 2020 जनजातीय शिक्षा में नवाचार और सुधार का मार्ग प्रशस्त करती है, जो उनके सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में सहायक होगी और उन्हें आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगी।

मुख्य बिंदु

1. **मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 5 तक) पर जोर -** NEP 2020 के अनुसार, कक्षा पांच तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। शोध से पता चलता है कि बच्चे पहली भाषा में पढ़ाई करने पर अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझते और सीखते हैं। मातृभाषा आधारित शिक्षा से बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं और वे शिक्षा में सफल होते हैं। साथ ही, यह नीति बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करती है और भाषा एवं सांस्कृतिक संरक्षण को भी बढ़ावा देती है।
2. **जनजातीय संस्कृति और परंपरागत ज्ञान को पाठ्यक्रम में समाविष्ट करना -** NEP 2020 शिक्षा के माध्यम से जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और परंपरागत ज्ञान को संरक्षित करने का प्रयास करती है। पाठ्यक्रम में स्थानीय संस्कृति, विधाओं, कला, और ज्ञान को शामिल कर बच्चों को उनकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना लक्ष्य

है। इससे बच्चों में सांस्कृतिक गर्व विकसित होता है और शिक्षा उनके जीवन के पर्याय बनती है।

3. **शिक्षक प्रशिक्षण को जनजातीय छात्रों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना -** शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे जनजातीय छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और शिक्षा संबंधी चुनौतियों को समझ सकें। संवेदनशील और समावेशी शिक्षण पद्धतियाँ अपनाकर शिक्षकों को जनजातीय समुदाय के छात्रों को बेहतर तरीके से मार्गदर्शन करना सिखाया जाएगा।
4. **डिजिटल शिक्षा के माध्यम से दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा पहुँचाना -** NEP 2020 डिजिटल तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देती है ताकि जनजातीय और दूर-दराज के क्षेत्रों के बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच सके। इससे भौगोलिक बाधाओं को पार कर शिक्षा के संसाधनों का वितरण आसान होगा। डिजिटल माध्यम से शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षकों की पहुँच बढ़ेगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधार होगी।
5. **ब्रिजिंग कोर्स और उपचारात्मक शिक्षा के आश्वासन से पिछड़े छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ना-** नीति के तहत ब्रिजिंग और उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था की गई है जिससे पिछड़े और पिछली कक्षाओं के क्षमता अनुसार छात्रों को मदद मिल सके। यह उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में प्रभावी ढंग से शामिल होने में सहायता करता है और शिक्षा में छूट को कम करता है।
6. **छात्रवृत्ति, आवासीय स्कूल और अन्य सहायता योजनाएँ -** NEP 2020 जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि आर्थिक बाधाओं के कारण उनकी शिक्षा में रुकावट न हो। यह उपाय आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हैं।

इस प्रकार, NEP 2020 की यह व्यवस्था जनजातीय शिक्षा के लिए एक समग्र, संवेदनशील और आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और समावेशन को सुनिश्चित करती है।

चुनौतियाँ

1. **भौगोलिक और संसाधन संबंधी असुविधाएं -** जनजातीय क्षेत्रों की भौगोलिक दूरी और कठिन क्षेत्रीय स्थितियाँ शिक्षा के सस्ते और सुगम वितरण में बाधा उत्पन्न करती हैं। सीमित संसाधन, अविकसित आधारभूत संरचना, और अपर्याप्त वित्तीय सहायता के कारण नीति का पूर्ण क्रियान्वयन कठिन होता है। दूरदराज के स्कूलों में शिक्षकों की कमी और शैक्षिक सामग्री की अनुपलब्धता भी समस्याएँ हैं।
2. **सांस्कृतिक विविधता व भाषा बाधाएं -** अनेक आदिवासी समुदायों की अलग-अलग भाषाएँ और सांस्कृतिक परंपराएँ हैं, जिन्हें शिक्षा नीति में समुचित स्थान देना आवश्यक

ISSN (Online): 3107-6165

है। मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान तो है, पर कई क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री एवं शिक्षकों की कमी है, जिससे भाषा जुड़ी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सांस्कृतिक बाधाएँ भी शिक्षा ग्रहण में अवरोध बनती हैं, क्योंकि पारंपरिक मान्यताएँ आधुनिक शिक्षा पद्धतियों से मेल नहीं खाती।

3. **नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक पहुँच में दिक्कतें -** नीति तो सम्पूर्ण और समावेशी है, परन्तु इसे स्थानीय स्तर पर लागू करने में कई प्रशासनिक और व्यवहारिक चुनौतियाँ आती हैं। लाभार्थियों तक योजनाओं का सही साधन से पहुंचना सुनिश्चित करना मुश्किल है। कम जागरूकता, भ्रष्टाचार, और कमजोर प्रशासनिक तंत्र से नीति के लाभों का अधिकतम उपयोग नहीं हो पाता। इसके अलावा, डिजिटल अवसंरचना की कमी भी दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाने में बाधा डालती है।

ये चुनौतियाँ NEP 2020 के जनजातीय शिक्षा क्षेत्र में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों, बेहतर संसाधन प्रबंधन और संवेदनशीलता का विकास आवश्यक है।

सुझाव

1. **स्थानीय भाषा में अध्ययन सामग्री और शिक्षण पद्धतियों का विकास -** शिक्षा सामग्री एवं शिक्षण प्रक्रियाओं को स्थानीय भाषाओं और बोली में विकसित करना जरूरी है, जिससे बच्चों की सीखने की क्षमता व समझ बेहतर होती है और सांस्कृतिक विरासत बनी रहती है।
2. **स्थानीय शिक्षकों की नियुक्ति जो सांस्कृतिक और भाषाई समझ रखते हों -** ऐसे शिक्षक नियुक्त किए जाएँ जो जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विशिष्टताओं और भाषाई जरूरतों से परिचित हों, जिससे वे संवेदनशीलता के साथ शिक्षा दे सकें और बेहतर संवाद स्थापित कर सकें।
3. **सामुदायिक सहभागिता के लिए जागरूकता अभियान आयोजित करना -** स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाकर अभिभावकों और समुदाय को शिक्षा के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए, जिससे शिक्षा में भागीदारी और नियमितता बढ़े।
4. **डिजिटल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण -** पिछड़े एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना विकसित कर शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए, जिससे आधुनिक तकनीकों के माध्यम से शिक्षा के संसाधन उपलब्ध हों।
5. **समय-समय पर नीति की समीक्षा और सुधार -** नियमित अंतराल पर नीति की समीक्षा कर उसमें सुधार करना आवश्यक है ताकि बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार शिक्षा प्रणाली को अपडेट किया जा सके और प्रभाव बढ़ाया जा सके।

ये सुझाव NEP 2020 की सफल कार्यान्वयन और जनजातीय शिक्षा के समावेशी विकास के लिए अति आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) जनजातीय शिक्षा के क्षेत्र में समावेशन और गुणवत्ता दोनों को बढ़ावा देने वाली एक क्रांतिकारी और व्यापक नीति है। यह नीति आदिवासी छात्रों की शिक्षा स्तर को सुधारने ही नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक समावेशन के उचित अवसर प्रदान करने का भी वचन देती है। NEP 2020 में विशेष रूप से मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है, जिससे बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में शिक्षा प्राप्त हो और शिक्षा का प्रभावी विकास हो सके। साथ ही, इसका ध्यान सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर भी है, जिससे जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रह सके और उन्हें शिक्षा के साथ-साथ अपनी परंपराओं को भी बनाए रखने का अवसर मिले। नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सतत् प्रयास, संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन और सांस्कृतिक समझ आवश्यक है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच दोनों सुनिश्चित की जा सकें। डिजिटल शिक्षा के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ शिक्षकों का प्रशिक्षण और स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री का विकास भी इसे और अधिक प्रभावशाली बनाता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक जागरूकता और स्थानीय समुदाय की भागीदारी नीति को सफलता की और ले जाने में सहायक होगी।

इस प्रकार, NEP 2020 न केवल जनजातीय छात्रों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है, बल्कि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करती है। यह नीति जनजातीय समाज के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत आधारशिला है, जिससे वे समान अवसरों के साथ देश के निर्माण और विकास में सक्रिय भागीदार बन सकेंगे। सतत सुधार, स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन और व्यापक भागीदारी से ही यह नीति पूर्ण रूप से सफल हो पाएगी और भारत की समावेशी शिक्षा प्रणाली को सशक्त करेगी।

संदर्भ सूची

1. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2020), *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय प्रकाशन। खंड 1, अध्याय 2, पृ. 45-68।
2. तिवारी, रजनीकांत। (2021), *जनजातीय शिक्षा और नई शिक्षा नीति का समन्वय,* भोपाल: आदिवासी अध्ययन केंद्र प्रकाशन। खंड 2, अध्याय 4, पृ. 92-115।
3. मिश्रा, एस. के। (2022), "नई शिक्षा नीति 2020 का जनजातीय शिक्षा पर प्रभाव", *भारतीय शिक्षा अनुसंधान पत्रिका,* खंड 14, अंक 3, पृ. 56-74।
4. पटेल, अंजना। (2021), *समावेशी शिक्षा और आदिवासी सशक्तिकरण,* रायपुर: छत्तीसगढ़ शिक्षा अकादमी। खंड 3, अध्याय 5, पृ. 132-154।

5. यूनेस्को। (2020), *Inclusive Education and Indigenous Communities in India,* पेरिस: यूनेस्को प्रकाशन। खंड 2, अध्याय 3, पृ. 80-103।
6. शर्मा, रेखा। (2019), *भारत में जनजातीय शिक्षा की स्थिति और सुधार की संभावनाएँ,* वाराणसी: ज्ञान भारती प्रकाशन। खंड 1, अध्याय 4, पृ. 66-88।
7. त्रिपाठी, महेश। (2021), "नई शिक्षा नीति और आदिवासी समाज में शिक्षा की गुणवत्ता", *शिक्षा विमर्श जर्नल,* खंड 12, अंक 2, पृ. 98-120।
8. बघेल, उर्मिला। (2023), *जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा में नीति-आधारित सुधार,* बिलासपुर: हिंदी ग्रंथ अकादमी। खंड 3, अध्याय 6, पृ. 171-193।
9. राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद। (2021), *Tribal Education and Policy Framework in India,* नई दिल्ली: एनसीईआरटी प्रकाशन। खंड 2, अध्याय 5, पृ. 145-168।
10. देवांगन, रेखा। (2022), *नई शिक्षा नीति और ग्रामीण-जनजातीय शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन,* रायपुर: शिक्षा सागर प्रकाशन। खंड 4, अध्याय 7, पृ. 202-224।
11. वर्मा, दीपक। (2020), "NEP 2020 के संदर्भ में जनजातीय युवाओं का कौशल विकास", *शिक्षा और विकास पत्रिका,* खंड 10, अंक 1, पृ. 39-57।
12. सिंह, मोहन। (2023), *Tribal Education in the Light of NEP 2020: Challenges and Opportunities,* नई दिल्ली: सामाजिक न्याय प्रकाशन। खंड 5, अध्याय 8, पृ. 230-254।